ग्राउंड जीरो : किसान आंदोलनों की जमीन से : पश्चिमी उत्तर प्रदेश

गन्ने के बकाया भुगतान का छलका दर्द, पर निगाहें बड़े मुद्दों पर भी

किसान बोले- खेती-बाड़ी के साथ-साथ सियासत पर भी है नजर

नितिन यादव

दिल्ली बॉर्डर से बागपत तक। किसान तड़के उठकर खेत में जाता है और फिर उसकी मंजिल गन्ना मिल या तौल केंद्र। उसमें किए तमाम वादे और अन्नदाता की अनेक इच्छाओं का चक्र रोज ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन, किसान अब खेत खलिहान से इतर भी सोचता है। ऐसा कहते हुए बागपत चीनी मिल के पास गन्ना लेकर पहुंचे गांव बली के किसान रविंद्र पंवार के चेहरे पर अलग भाव नजर आते हैं। दरअसल, चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत का दौर देख चुके गन्ना बेल्ट के किसान बस वोटर नहीं रहना चाहते। गन्ना भुगतान न मिलने और उपेक्षा से वह दुखी तो हैं, लेकिन राजनीति को भी नजदीक से देख रहे हैं। उसे यह कहलाना पसंद नहीं कि वह किसी बिरादरी या पार्टी का वोटर है। यही वजह है कि चौधरी अजित सिंह के प्रभाव वाली किसान और जाट बेल्ट में लोग पीएम मोदी के चेहरे की ओर भी देख रहे हैं।

किसान बेल्ट में रोचक होगी चुनावी जंग

बकाया भुगतान पर सभी सरकारों के वादे अधूरे

मोदीनगर मिल पर गन्ना डालने आए गाजियाबाद के चितौड़ा निवासी मनोज चौधरी साफ कहते हैं कि गांव-किसानों के साथ सालों से छल होता आ रहा है। विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों ने कसमें खाकर वादे किए थे। उन पर भरोसा कर वोट तो दे दिया, लेकिन इस साल का काफी भुगतान रुका हुआ है। हम ऐसे नेताओं से उनके वादों का हिसाब मांगेंगे। गांव जलालबाद के किसान कपिल का कहना है कि हर जगह कोई सामान खरीदने के लिए पहले पैसा देना पड़ता है तो किसानों को अपने पैसे के लिए क्यों इंतजार करना पड़ता है।

किसानों की चुनावी प्राथमिकता-मजबूत सरकार

दिल्ली से जैसे-जैसे गन्ना बेल्ट की ओर आगे बढ़े तो किसानों के मुद्दे और देश की राजनीति पर लोगों की राय और रोचक होती चली गई। मेरठ की मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल के बाहर किसान ट्रैक्टर और बुग्गियों में गन्ना लेकर खड़े हैं। गांव छज्जूपुर निवासी सुनील कुमार के पास करीब 20 बीघा जमीन है। उनका अभी जनवरी तक का ही भुगतान हुआ है। कहते हैं कि 15 दिन में भुगतान के वादे खोखले साबित हुए हैं। वोट किसे करेंगे, इस पर वह कहते हैं- देश में इससे भी बड़े मसले हैं। देश को मजबूत सरकार चाहिए। पास में ट्रैक्टर पर बैठे 35 साल के किसान अंकित कहते हैं कि किसान भी अब चाहता है कि दुनियाभर में देश की नुमाइंदगी मजबूत हो। मेरठ से बागपत रोड पर गांव बाफर के गन्नातौल केंद्र पर बैठे युवा किसान कुलदीप सिंह का कहना है कि किसानों को अब किसी एक के पीछे नहीं हांका जा सकता है। वह दूसरे मुद्दों पर भी निगाह रखता है।

किसान बेल्ट से चलती रही है हवा

गन्ना बेल्ट में पश्चिम की कई महत्वपूर्ण सीटें है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, कैराना, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद जैसी सीटों पर गन्ना किसान निर्णायक स्थिति में है। पिछले चुनाव में भाजपा ने यह सभी सीटें जीत ली थीं। पहले चरण के चुनाव में यहां से चली हवा के बाद ही भाजपा ने पूरे प्रदेश में दूसरे दलों को बुरी तरह से हराया था।

2017 में गन्ना किसानों का 6401 करोड़ बकाया था, 2019 में 12472 करोड़

19 मार्च 2017

यानी योगी सरकार के आने से पहले तक कुल देय गन्ना मूल्य 21577.48 करोड़ रुपये के सापेक्ष 15168.07 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। यह कुल देय गन्ना मूल्य का 70.30 फीसदी था। बकाया गन्ना मूल्य 6401.4 करोड़ रुपये था।

19 मार्च 2019

चालू पेराई सीजन 2018-19 के कुल देय गन्ना मूल्य 24609.98 करोड़ रुपये के सापेक्ष 12137.72 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। यह कुल देय गन्ना मूल्य का 49.32 प्रतिशत है। बकाया गन्ना मूल्य 12472.26 करोड़ रुपये है।

सभी बड़े चीनी मिल समूह

बकायेदार

बजाज समूह : चालू सत्र में मात्र 12% भुगतान, 3304 करोड़ बकाया

मवाना समूह: मात्र 24% ही भुगतान। समूह पर किसानों का 444 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य अवशेष है।

मोदी समूह: मात्र 13% भुगतान किया है। 386 करोड़ बकाया है।

राणा समूह : कुल बकाया गन्ना मूल्य 433 करोड़ (63%) है।

सिंभावली समूह: भुगतान शून्य। 556 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया।

यदु समूह: भुगतान मात्र 4.17 करोड़ रुपये। बकाया 143 करोड़।

वेव समूह: कुल बकाया 323 करोड़

उत्तम समूह: बकाया गन्ना मूल्य 313 करोड़ (57 फीसदी)